(c) No assistance is specifically extended for the implementation of housing programmes in urban development projects assisted by the World Bank. Howew, the urban development projects include *inter-alia* sites & services component wluch^provides for development ©f services, residential, commercial and small industry plots including community facilities, core housing and home improvement/shelter loans and slum upgradation component. Under the Bombay Urban Development Project an amount of dollar 120. 045 million vras allocated under land an'd infrastructure servicing programmes, slum upgradation programme and home improvement loans. For the Gujarat Urban Development Project an amount of dollar 8. 97 million h«« been allocated for Sites anj Services and for Slum Upgradation programme.

**Irrigation in Maharashtra**

2229. SHRI NARESH C PUGLIA: Will the Minister of WATER RESOURCES be~pleased t© state:

(a) the area of land brought under irrigation in 1986 and proposed to be brought under irrigation during 1987-88 in Maharashtra in general and Vidarbha in particular; and

(b) the details of the financial assistance to be given for the areas proposed to be brought under irrigation in Vidarbha and other parts of Maharashtra?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. * SHANKARANAND): (a) Land Use Statistics for the year 1986 are not available. However, a gross cropped area of about 2. 91 m. ha. is expect-: d to be under irrigation by end of 1986-87. The target for 1987-88 is yet o be finalised. Details of achievements m'd targets in the regions within a State ire not maintained at the Centre.

(b) Irrigation schemes are planned, undej and implemented by State Govern-lents arid Central assistance is given in le form of block grants and. loans and i not tied to any scheme or sector of de-slopment.

**हरिजन/आदिवासी परिवारों के लिए आवास**

2230. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अनुमानत: कितने हरिजन आदिवासी परिवारों के पास रहने के लिये मकान नहीं हैं ;

(ख) क्या उन्हें आवास उपलब्ध कराने के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की योजना में केन्द्र व राज्यों की कितनी भागीदारी होगी ;

(घ) प्रतिवर्ष कितने आवासों का निर्माण किये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) उन पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) से (ङ) "आवास" राज्य का विषय होने के नाते सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं । अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित ग्रामीण भूमिहीन कामगरों के लिए आवास स्थलों के आवंटन तथा निर्माण सहायता की योजना राज्य योजना निधियों में से वित्त-पोषित की जाती है तथा इस योजना के अन्तर्गत परिवारों के लाभान्वयन के लक्ष्य वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते हैं इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त किए गये बन्धुवा मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण के लिए इन्दिरा आवास योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के भाग के रूप में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई है तथा